मीडियाकर्मियों के लिए जिला योजनाओं के विकेंद्रीकरण पर कार्यशाला, सुदेश ने कहा

साझेदार और भागीदार के रूप में रहे मीडिया

यूनाइटेड नेशन, झारखंड सरकार और इनक्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की ओर आयोजित की गयी थी कार्यशाला.

मीडियाकर्मियों और पंचायत व नगरपालिका के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया

वरीय संवाददाता ■ रांची

राज्य के उप मुख्यमंत्री सह ग्रामीण विकास मंत्री सुदेश महतो ने कहा है कि मीडिया को विकास में साझेदार और भागीदार के रूप में हिस्सेदार होना चाहिए. व्यवस्था में हो रहे गुणात्मक बदलाव की निगरानी रखनी चाहिए. व्यक्तिगत आक्रमण और पूर्वाग्रह की खबरों से बचना चाहिए. सबमें कमी होती है. कोशिश करनी चाहिए कि विकास में सहयोग करें.

श्री महतो सोमवार को यूनाइटेड नेशन, राज्य सरकार और इनक्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की ओर से मीडियाकर्मियों के लिए आयोजित जिला योजनाओं के विकेंद्रीकरण विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. दो दिनों की कार्यशाला में झारखंड के कई जिलों के चयनित मीडियाकर्मी और पंचायत तथा नगरपालिका की निर्वाचित प्रतिनिधियों को बुलाया गया है. पहले सत्र की अध्यक्षता पत्रकार हरिवंश ने की. उप मुख्यमंत्री श्री महतो ने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाना है, तो जनशक्ति को सशक्त बनाना होगा. जनशक्ति को मजबूत बनाने के लिए उनकी भागीदारी और साझेदारी को सशक्त करना होगा. राज्य में संभावनाओं की कमी नहीं है. जब तक ग्राम सशक्त नहीं होंगे, नये भारत का निर्माण नहीं हो सकता है. केवल मुखिया का पंचायत समिति के सदस्य चुने जाने से ग्रामसभा पूरी नहीं होगी. ग्रामसभा को जनता के विश्वास पर खरा उतरना होगा. योजनाओं को ग्राम सभा से बना कर केंद्र के पास भेजना चाहिए. केंद्र को अपनी योजना सभी राज्यों को नहीं थोपनी चाहिए, क्योंकि यह कोई जरूरी नहीं की केरल की प्राथमिकता झारखंड के लिए भी जरूरी हो. जरूरी यह है कि आम लोगों की जरूरत कैसे पूरी हो. जो राशि खर्च हो रही है, वह गांवों तक जाये. राज्य सरकार ने 100 गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने की ठानी है. सरकार चाहती है कि इसमें मीडिया सहयोगी की भूमिका में रहे. वह भी सुझाये कि इन गावों को बेहतर मॉडल क्या हो सकता है.

मंत्री ने कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है. कमियों के बीच ही रास्ता निकालना है. अभी तब बीपीएल की परिभाषा तय नहीं हुई है. बीपीएल की गणना स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए. राज्य सरकार आर्थिक गणना के माध्यम से एक नया रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है.

सत्ता का एजेंसीकरण हुआ है : टीआर रघुनंदन

भारत सरकार के पूर्व संयुक्त सचिव सह यूएनडीपी के सलाहकार टीआर रघुनंदन ने कहा कि अभी जो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात हो रही है, इसके पीछे की मंशा साफ नहीं है. इसमें राजनीति है. अभी सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं, एजेंसीकरण हुआ है. देश के अधिकारी नहीं चाहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो. उनको अपनी सत्ता जाने का डर होता है. आज एक भी जिला अधिकारी के पास नहीं है. एक जिला अधिकारी का औसतन सेवा काल 14 महीने से कुछ अधिक है. 60 से लेकर 100 कमेटियों में वह सदस्य होते हैं. फिर भी वह नहीं चाहते हैं कि गांव की सत्ता उनके काम में हस्तक्षेप करे. सिविल सोसाइटी की भूमिका भी संदिग्ध हो गयी है. वह भी सरकार के इर्द-गिर्द रहने लगी है. उन्होंने कहा कि झारखंड ने अपनी पंचायत को बहुत शक्ति दी है. यह कई अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है. एक बहुत अच्छी बात है कि पंचायती राज में यहां के पारंपरिक नेता को भी अधिकार दिया गया है. लेकिन, अधिकारियों की स्थिति अच्छी नहीं है. राज्य के प्लान पर जून में चर्चा हुई है. यह मार्च में होनी चाहिए थी.

प्रतिनिधि हुए तो जनता से ही डर लगने लगा : डॉ शरण

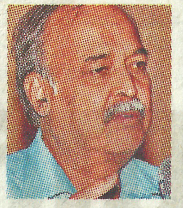

जाने-माने अर्थशास्त्री डॉ रमेश शरण ने कहा कि जब से राज्य में पंचायतों के चुनाव हुए हैं, स्थिति और बदल गयी है. पैदल और साइकिल पर चलनेवाले जिला परिषद के सदस्यों ने चुनाव जीतते ही पहले गाड़ी खरीद ली. उसमें जिला परिषद अध्यक्ष का बोर्ड लगा दिया. अब बॉडीगार्ड मांगने लगे हैं. जिस जनता ने उन्हें जिताया है, उसी से डर लगने लगा है. उनके रवैये में भी बदलाव हो गया है. चुने हुए प्रतिनिधियों के रवैये में बदलाव के बिना विकास भी संभव नहीं है. डॉ शरण ने कहा कि पेसा जैसा कानून पांच-छह लोगों की उपज है. इस संबंध में जब एक सांसद से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि इसमें आदिवासियों की बाते हैं. उनको इस कानून की गंभीरता के बारे में भी नहीं पता था. यहीं कारण है कि सदन में बिना विरोध के यह पारित हो गया. यहीं आज गांव में हो रहा है. उनके हिसाब से योजनाएं नहीं बन रही हैं. असल में लोग जिस विकेंद्रीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, वह आसान नहीं है. गांव के लोग आज जिस सत्ता के विकेंद्रीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, वह आसान नहीं है.

विशेषज्ञों ने कहा

पंचायतों के पास नहीं है तकनीकी विशेषज्ञ : मिश्रा

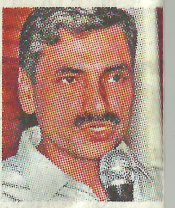

सीडीडीपी के जिला प्लानिंग के विशेषज्ञ सुंदर एन मिश्रा का मानना है कि पंचायती राज व्यवस्था के पास योजना तैयार करने की कोई विशेषज्ञता नहीं है. उनके बात तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं. यही स्थिति शहरी निकायों के साथ भी है. कोशिश होनी चाहिए कि इनको तकनीकी और आर्थिक रूप से सक्षम किया जा सके. ऐसा होने से ही सत्ता के विकेंद्रीकरण का फायदा होगा.

बहुत कुछ करने की जरूरत : विपुल मुदगल

सीएसडीएस, नयी दिल्ली के निदेशक डॉ विपुल मुदगल ने कहा कि प्रजातंत्र के मॉडल में मीडिया भागीदार नहीं होगी, तो वह काफी पीछे रह जायेगी. यहां भी सत्ता, समाज और शासन का विकेंद्रीकरण हो रहा है. अभी भी देश में प्रजातंत्र में लोकसहभागिता की दिशा में बहुत कुछ करना है. देश के कई राज्यों में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है. सभी अपने-अपने स्तर से गांव के शासन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं.

कागज पर सत्ता विकेंद्रीकरण : सुधीर पाल

मंथन युवा संस्थान के सुधीर पॉल ने कहा है कि राज्य में सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात हो रही है. पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव हुए. लेकिन, सच्चाई यह है कि कागज पर सत्ता का विकेंद्रीकरण तो हुआ, लेकिन सच्चाई कुछ और है. पंचायत तो बन गयी है, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिला है. कोई तकनीकी सहयोग नहीं है. राज्य में एक अच्छी बात है कि यहां जिला योजना समिति के अध्यक्ष मंत्री हैं. बिहार में जिला परिषद अध्यक्ष ही अध्यक्षता करते हैं. इसका फायदा भी है, नुकसान भी. राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के संचालन के लिए वित्त आयोग का तो गठन कर दिया है, लेकिन वह फंक शन में नहीं है. जिला योजना कमेटी के नीचे छह सब कमेटी बननी थी, ऐसा नहीं हुआ है. पंचायतों को कोई कस्टमरी अधिकार भी नहीं दिये गये हैं. इस कारण व्यवस्था और सच्चाई में काफी अंतर हैं.

सुनना आसान, करना मुश्किल : अविनाश कुमार

राज्य में योजना एवं विकास विभाग के सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि योजना से सूत्रण ऐसी कला है, जो सुनने में तो आसान है, लेकिन यह काफी जटिल है. जब तक इसकी जटिलता को नहीं समझा जायेगा, सही ढंग से योजना नहीं बन सकती है. इसमें कल आज और कल का तालमेल होता है. इसका आकलन करने के बाद ही योजनाओं की बेस लाइन तैयार होती है. मीडियाकर्मियों को भी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए. मीडिया को भी सजग रहने की जरूरत है. मीडिया सजग नहीं होगी, जो डेमोक्रेसी भी पूरी नहीं होगी.